plants in their constituencies, must be given the chance to speak something, because they know the subject. They have to bear the brunt of it.

MR. SPEAKER: That is not a point of order. Now Mr. Ramanand Tiwary.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): On a point of order.

MR. SPEAKER: On every question you are rising.

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER: Don't record.

*(Interruptions)***

12.30 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

(i) REPORTED CRITICAL POSITION IN SUPPLIES OF FURNANCE OIL TO INDUSTRIAL UNITS AND NON-AVAILABILITY AND HIGH PRICES OF KEROSINE OIL

श्री रामानन्द तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "देश में, विशेषकर बम्बई क्षेत्र में, विभिन्न औद्योगिक एककों को भट्ठी-तेल की सप्लाई संबंधी चिन्ताजनक स्थिति और देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी का तेल उपलब्ध न होने तथा महंगे दामों पर बिकने के समाचार"।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : महोदय, माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान देश में, विशेषकर बम्बई क्षेत्र में, औद्योगिक यूनिटों को भट्ठी के तेल की सप्लाई के संबंध में तथाकथित विकट स्थिति तथा देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता और अधिक मूल्यों की ओर आकर्षित किया है।

भट्ठी के तेल की खपत में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। यद्यपि पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1975-76, 1976-77 तथा 1977-78 में खपत की वृद्धि दर निषेधात्मक रही है, अप्रैल 1978 से फरवरी, 1979 की अवधि के दौरान खपत की दर में वृद्धि पिछले वर्ष के तदनुरूपी अवधि की बिक्री से 8 प्रतिशत अधिक रही है। खपत की दर में बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से खपत वाले स्थानों पर कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण दिखलाई दी।

देश में भट्ठी के तेल की कुल आवश्यकता का लगभग 25 प्रतिशत आयात द्वारा पूरा किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अशान्त स्थिति को देखते हुए भट्टी के तेल और मिट्टी के तेल की आवश्यक मात्रा का आयात करना संभव नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त रेल द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों को ढोने के लिए पिछले एक वर्ष या इससे अधिक की आवश्यकता की तुलना में कमी रही है। बंदरगाहों और बरौनी रिफाइनरी में श्रमिक समस्याओं तथा अन्य कई आकस्मिक कारणों से देश की शोधनशालाओं में कच्चे तेल के थ्रुपुट में भी हानि हुई है। यद्यपि इन कठिनाइयों पर इस मंत्रालय अथवा तेल कम्पनियों का कोई नियंत्रण नहीं था, तो भी पिछले वर्ष की तुलना में भट्टी के तेल की सप्लाई उच्च स्तर पर करना संभव हो सका है। परन्तु देश के कुछ भागों से भट्ठी के तेल की उपलब्धता के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कि कोयले की कमी के कारण मांग में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं।

बम्बई बंदरगाह में श्रमिक समस्याओं के कारण टैंकरों से कच्चा तेल उतारने के काम में रुकावट के कारण बम्बई शोधनशाला में फरवरी और मार्च के दौरान भट्ठी के तेल तथा अन्य पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इसके परिणामस्वरूप, मार्च में बम्बई में भट्ठी के तेल की उपलब्धता में ससम्याएं उत्पन्न हो गयी थीं। परन्तु मार्च के अन्तिम सप्ताह से बम्बई की शोधनशालाएं पूर्व निर्धारित स्तर पर उत्पादन कर रही हैं और आयातित उत्पाद भी पहुंच चुके हैं। आशा है कि इस से स्थिति के सुधरने में सहायता मिलेगी।

परन्तु इस संबंध में यह बताना आवश्यक होगा कि औद्योगिक तथा विद्युत क्षेत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता में कमी को पूर्णरूप से पूरा करने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा भट्ठी के तेल की पूरी सप्लाई करना संभव नहीं होगा। परन्तु कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की कुल उपलब्धता और परिवहन सक्षमताओं की कठिनाइयों की परिसीमाओं में इस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न जारी रखे जायेंगे।

**Not recorded.

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुना]

12.33 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

जहां तक मिट्टी के तेल का संबंध है, देश की कुल खपत का 40 प्रतिशत इस समय आयात किया जाता है। व्यापार योजना के अन्तर्गत सोवियत संघ से इस उत्पाद की प्राप्ति में विलम्ब के कारण देश में मिट्टी के तेल की समस्त उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार तथा तेल कम्पनियों के अधिकतम प्रयत्नों के बावजूद इस उत्पाद का अन्य संसाधनों से पर्याप्त आयात प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है। फिर भी, अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 की अवधि के दौरान मिट्टी के तेल का विक्रय पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। मिट्टी के तेल की अधिक मांग भी कोयला, साफ्ट कोक तथा जलाने वाली लकड़ी जैसे वैकल्पिक इंधन की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण ही है। पिछले वर्ष की बिक्री की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान मिट्टी के तेल का विक्रय अधिक होने के बावजूद देश के विभिन्न भागों से ये रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि मिट्टी के तेल की कमी महसूस की जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस उत्पाद की उपलब्धता बहुत कठिन है, इस बात को देखते हुए देश में मिट्टी के तेल की असीमित मांग को पूरा करना संभव नहीं हो सका है जबकि तेल कम्पनियां मिट्टी के तेल की सप्लाई अपने एजेंटों को निर्धारित आवंटन के अनुसार करती है, परन्तु इसके वितरण की देखरेख पूर्णरूप से राज्य सरकारों का दायित्व है। हमने राज्य सरकारों को पहले ही यह परामर्श दिया है कि वे इस उत्पाद के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करें। जिससे यह उत्पाद काले बाजार में न जाये। मेरे मंत्रालय का यही प्रयत्न है कि विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्धारित आवंटन के अनुसार मिट्टी के तेल की सप्लाई सुनिश्चित की जाये। अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 की अवधि के दौरान मिट्टी के तेल का कुल विक्रय 3.63 मिलियन मी0 टन था जबकि इसका आवंटन 3.59 मिलियन मी0 टन था।

जहां तक पूर्वी उत्तर प्रदेश का संबंध है, मार्च महीने के दौरान कुल लगभग 22,000 किलो लीटर मिट्टी का तेल दिया गया था जबकि इसके लिए आवंटन 19,000 किलो लीटर का था। परन्तु मार्च के दौरान हल्दिया में मिट्टी के तेल का आयात कम रहा जो कि बिहार के कुछ भागों को मिट्टी के तेल की सप्लाई करती है। इसके फलस्वरूप, बिहार के कुछ क्षेत्रों में निर्धारित आवंटन के अनुसार मिट्टी के तेल की सप्लाई करने में समस्याएं उत्पन्न हो गयी थीं। मार्च के अंतिम सप्ताह से हल्दिया में आयातित मिट्टी का तेल पहुंचना शुरू हो गया है और आशा है कि इस उत्पाद की सप्लाई बिहार को निर्धारित आवंटन के अनुसार की जायेगी।

श्री रामानन्द तिवारी : ऐसा लगता है कि जिस तरफ हमने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। मैंने यह कहा था कि भट्टी-तेल का बम्बई में इतना अभाव है कि वहां काम करना मुश्किल हो गया है। मैंने यह भी कहा था कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिटटी का तेल नहीं मिल रहा है और यदि मिलता है तो 4-5 रुपए लीटर। मंत्री जी के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि सरकार जनता को भट्टी-तेल और मिट्टी का तेल पहुंचाने में असमर्थ है। मैं जानना चाहता हूं इस वित्तीय वर्ष के पहले क्या कारण था कि आसानी से भट्टी और मिट्टी का तेल मिलता था लेकिन इस बजट के आने के बाद तेल मिलना दुर्लभ हो गया है और यदि मिलता भी है तो तीन, चार या पांच रुपए लीटर ? कोई प्रश्न आता है तो सरकार कहती है कि कोयले का अभाव है। हम जानना चाहते हैं कोयले के अभाव को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया जिस से कि कोयले की आपूर्ति हो सके। यह एक बड़ी दुःखद स्थिति है क्योंकि मिट्टी का तेल कौन जलाता है ? मिट्टी का तेल बड़े बड़े लोग तो जलाते नहीं हैं क्योंकि उनके यहां विद्युत् है। लाखों किसान, खेतिहर मजदूर, झोपड़ी वाले, रिकशा चलाने वाले तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी मिट्टी का तेल जलाते हैं। आज मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है जिसके परिणामस्वरूप उनको भूखों मरना पड़ रहा है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में गांव के गांव अंधकार में हैं। चोरी डकैती से बचने के लिए भी रोशनी नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कारण है कि वही तेल चोरबाजारी में 4-5 रूपये लीटर मिल जाता है ? मैं जानना चाहता हूं बिहार में क्या कोई विधि व्यवस्था है, क्या वहां पर कोई कानून का राज है ? वहां पर मनमानी स्थिति चल रही है। कोई व्यक्ति दिन में चल नहीं सकता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मिट्टी का तेल किस तरह से वितरित किया जाये, किस प्रकार से वह गरीबों को उपलब्ध हो सके—इसकी व्यवस्था केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले क्योंकि बिहार सरकार इसमें बिल्कुल असमर्थ है। दूसरी बात यह है कि अगर मिट्टी का तेल नहीं है तो चार-पांच रुपए लीटर के भाव पर चोर बाजार में क्यों मिल रहा है और चोरबाजारी करने वालों को पकड़ने की व्यवस्था आप क्यों नहीं करते हैं ? बिहार सरकार से यह काम नहीं हो सकता है। मैं मंत्री जी से साफ तौर से जानना चाहता हूं कि मिट्टी का तेल उचित दाम पर क्यों नहीं मिल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी वही स्थिति है जहां के माननीय मंत्री जी रहने वाले हैं। बम्बई की भी वही स्थिति है। सकारर कहती है कि

आयात नहीं हो पायेगा तथा कोयले का अभाव है, ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल असमर्थ है। लाखों करोड़ों गरीबों की झोपड़ियों में चिराग नहीं जल रहे हैं। आखिर उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उपाध्यक्ष जी, मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो यह है कि यह कहना कि बाम्बे क्षेत्र में तेल के उत्पादों की अनुपलब्धता न होने के कारण कारखाने बन्द हो गए, डी जी टी डी से हमने जांच करवाई है उनकी रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक कारखाना रबड़ का है, उसको छोड़ कर कोई कारखाना बन्द नहीं हुआ है—यह 2 अप्रैल का खत है। माननीय सदस्य की आत्मा में लोगों के लिए नोशनल दुःख है उसके लिए तो मुझे सहानुभूति है लेकिन वास्तविकता के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ें तो दुःख बहुत कम हो जायेगा। एक रबड़ के कारखाने को धक्का लगा, बाकी कहीं कोई धक्का नहीं लगा, सभी कारखाने चलते हैं।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात यह कही कि मिट्टी के तेल के वितरण का इन्तजाम केन्द्रीय सरकार खुद करे। इस मामले में माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु का जो दल है उस की स्पष्ट राय है कि फैडरल-स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिये। अगर सब चीजों का बटवारा दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी हो, तब तो यूनीटरी-फार्म-आफ-गवर्नमेन्ट बनानी होगी। फैडरल स्ट्रक्चर में यह संभव नहीं है। हम ने राज्य सरकारों को इसी पीरियड में जितना मिट्टी का तेल पिछले साल दिया था, उस से कम दिया हो—सिवाय बिहार के एक भाग के—तो हम जिम्मेदार हैं....

श्री डी. एन. तिवारी : सब जगह पूरा दे रहे हैं तो बिहार को ही क्यों कम दिया जा रहा है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हल्दिया से तेल आता था। माननीय सदस्य इस सदन के सब से पुराने सदस्य हैं—उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि ईरान से हिन्दुस्तान को हर महीने मिट्टी का तेल साढ़े-पांच लाख टन मिलता था, जो नवम्बर, 1978 से बन्द है। अब ईरान के हालात को दुरुस्त करने के लिये यहां से कोई कोई बन्दोबस्त करने की सलाह तो मैं नहीं दे सकता, सिवाय इस के कि प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर हालात जल्दी से ठीक हों।

पूर्वी उत्तर प्रदेश को ले लीजिये—जिस वायदे की चर्चा माननीय सदस्य ने की है—उन को 22 हजार किलो-लिटर मिट्टी का तेल दिया है, जब कि वायदा 19 हजार किलो-लिटर का था, 3 हजार किलो-लिटर ज्यादा दिया। मैं यहां पर यह अवश्य कहना चाहता हूं कि मैं केरल की सरकार का कृतज्ञ हूं—इस का मतलब यह नहीं है कि मैं बाकी सरकारों की बुराई कर रहा हूं—लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था की है, उस के लिये वे बधाई के पात्र हैं। वे घर-घर में कार्ड से मिट्टी का तेल लोगों को दिलवा रहे हैं, इस तरह की वितरण व्यवस्था वहां पर चल रही है। मैं यह भी निवेदन कर दूं—मैंने देश भर के मुख्य मंत्रियों, को जिस समय ईरान में झगड़े होने शुरु हुए थे, अगस्त, 1978 में एक पत्र लिखा था....

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : झगड़ा नहीं, क्रांति कहिये।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यहां पर जो हो रहा है, वह भी क्रांति ही है—मिट्टी का तेल ज्यादा मिलना चाहिये। लेकिन मिट्टी का तेल भारत के पास कितना उपलब्ध है और कितना कितना भेजा जा सकता है—इस के लिये आप को हमारे साथ हमदर्दी करनी पड़ेगी और अपने साथ भी हमदर्दी करनी पड़ेगी। जैसा मैंने अभी कहा—मैंने प्रदेश की सरकारों का ध्यान इस की तरफ आकर्षित कराया था, उस के बाद हमारे सैक्रेटरी ने मुख्य-सचिवों का ध्यान आकर्षित किया। कल भी एक मीटिंग बुलाई थी, जिस में तमाम प्रदेश सरकारों के खाद्य सचिवों से सलाह की है। हम ने अपनी तरफ से इस को हर जगह पहुंचाने की चेष्टा की है। लेकिन इस में एक नुकसान हुआ है—जो हम ने ज्यादा दिया है, उस के कारण हमारी इन्वेन्टरी कम होती गई है। मुश्किल यह है कि सदन से कोई भी बात छिपाना हमारे लिये पाप है और वह उचित भी नहीं है। खुला समाज होने के कारण अखबारों में छपने से बचनेवाली बात नहीं है, इस लिये जो चतुर व्यापारी होंगे वे इस का लाभ उठा लेंगे ....

श्री दिनेश भट्टाचार्य (सीरमपुर) : उन चतुरों को पकड़ें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : पकड़ने का काम बंगाल में श्री ज्योति बसु जी का है और बिहार में श्री कर्पूरी ठाकुर जी का है, मेरा नहीं है। ज्योति बसु जी ने कितने तेल के व्यापारियों को पकड़ा है, ज्योतिर्मय बसु जी बतला दें, मैं तो नहीं जानता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पकड़ा है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : बहुत खुशी की बात है मुझे श्री ज्योति बसु साहब को लिखना पड़ा, जब उन्होंने मिट्टी के तेल के व्यापारियों के कहने में आ कर उन को दो पैसा ज्यादा दे दिया, मैंने कहा कि इस को कम करो। हम तो, आप देख लीजिये, इतना सचेष्ट रहते हैं, प्रदेश की सरकारों से

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

कोई गलती हो रही हो तो उन को याद दिलाते रहते हैं। हम सूबों की सरकारों की सहायता करने के लिये हमेशा तैयार रहते हैं।

माननीय सदस्य तिवारी जी से, जो हमारे बुजुर्ग भी हैं, एक ही प्रार्थना है कि देश की जो कठिनाई है, ईरान से कच्चा तेल न मिलने के कारण जो दिक्कत पैदा हो गई है, उस को समझा जाना चाहिये। हम कृतज्ञ हैं —एक देश के— मैं खास तौर से इस मौके पर उस का नाम लेना चाहता हूं—ईराक—जिस ने हम को मिट्टी का तेल देने में मदद की है। आज जब कि दूसरे देश यह कह रहे हैं कि कितने डालर एक बैरल पर और दोगे—उन्होंने हमारी मदद की है। अब मैं लीबिया जा रहा हूं—इस आशा से कि वे भी हमारी मदद करेंगे। कच्चा तेल जो हम को मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला और उसका का बन्दोबस्त करने में कमी आई है और इस के साथ ही यह बात भी है कि हमारा देश तो एक प्रजातान्त्रिक देश है। यहां पर कोई मंत्री यह नहीं कह सकता है कि किसी को स्ट्राइक का कोई हक नहीं होगा। हम कोशिश कर सकते हैं कि स्ट्राइक न हो लेकिन स्ट्राइक हो जाए, तो यह नहीं है कि स्ट्राइक-तोड़ सरकार हो। स्ट्राइकर्स के साथ बातचीत कर के स्थिति को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। हल्दिया में स्ट्राइक हो गया और हमारे टैंकर्स खड़े रह गये। इसी तरह से बम्बई में स्ट्राइक हो गया और टैंकर्स खड़े रह गये, 40 दिन तक हड़ताल चली और बात चीत करके जितनी जल्दी मामला सुलझ सकता था, उस को सुलझाया। मैं यह मान सकता हूं कि और अच्छा बन्दोबस्त होना चाहिए और "अच्छा" की एक ऐसी रेखा है, जिस तक पहुंचने के लिये बराबर चेष्टा करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि और भी अच्छा काम करना चाहिए लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की जो वर्तमान शासन व्यवस्था है, फेडरल जिस का रूप है, उस में मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था का कन्ट्रोल भारत सरकार अपने हाथ में लेने वाली नहीं है। यह काम तो प्रदेशीय सरकारों का है और हम ने इस बारे में उन को स्पष्ट कर दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर (दुर्गापुर) : हमारी स्टेट को इतना कम क्यों दिया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इतना कम, इतना कम, इतना कम की जो यह भाषा है, यह हमारी समझ में नहीं आती है। अगर मेट्रिक टन में बात करें, अगर यह बताएं कि इतने मेट्रिक टन मिलना चाहिए और इतना मिला है, तो मैं यह बता दूं कि वेस्ट बंगाल को जितना कोटा मिलना चाहिये, उस से ज्यादा मिला है। नार्थ ईस्ट के हमारे माननीय सदस्य अगर इस बात में मदद कर दें कि वहां हड़ताल न होने दें, बड़ी मुश्किल में हमारे रेल मंत्री महोदय आए हुए हैं, तो वहां पर उपलब्धता बढ़ सकती है। नार्थ बंगाल में उपलब्धता में जरूर कुछ कमी आई है वरना बंगाल का कोटा पूरा देने की हम ने पूरी कोशिश की है। मैं यह मानता हूं कि सारे देश में जो कमी है, उस के कारण इनवेंटरी में कमी हो रही है। इसलिए आने वाले समय में कठिनाई आने वाली है और इसी लिए हम ने सारे प्रदेशों के खाद्य सचिवों को बुलाया था और उनको यह बताया था कि कैरल के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पेटर्न जब तक आप नहीं लगा योगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि मिट्टी का तेल घरों तक और झोंपड़ियों तक और डीजल किसानों तक पहुंच सकेगा।

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur): I had raised this point by my Unstarred Question No. 3857 dated 20th March and drew the attention of the Government to the serious shortage of furnace oil in Bombay, particularly in the Thana-Belapur industrial complex. I also drew attention to the shortage of kerosene oil not in Bombay, but in other States, particularly Bihar, U.P. and Bengal. The hon. Minister, in reply to my question, stated:

> "The information is not readily available. The details are being collected, and the same will be laid on the Table of the House."

As the information has not been made available for such a long time, I gave this Calling Attention notice.

The hon. Minister has just now said in his statement that consumption of furnace oil has increased by 8 per cent in the last three years. In this connection, firstly I would like to

draw attention of the Minister to the fact that it is the policy of the Government to ask the industries to use more furnace oil because by using coal they will be polluting the air. So, they stopped using coal and have started using furnace oil.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Who told you that furnace oil does not pollute the air?

SHRI S. R. DAMANI: Therefore, the consumption of furnace oil has increased. There was no difficulty upto December. The supply was normal. It was available in required quantity. Since January, the things have started deteriorating. The hon. Minister, just now, said that according to the information available with him, no factory has been closed down on account of shortage of furnace oil. But I can give him names of many units which have closed down for 10 or 7 or 6 days in that industrial complex of Thana-Belapur because furnace oil was not available. I would not like to mention the names of those units now. But I can pass on all the names to him so that he can enquire about it. In February and March also, the position was very difficult. Some units have closed down for a fortnight. You can imagine the loss of production; you can imagine the loss of revenue and the result will be that there will be more shortage of the items which are produced by these unit. So, it is very necessary that this aspect should be examined and the measures taken to make available adequate quantities of furnace oil to the industrial units in a proper way so that they can continue to run their units.

I have got all the sympathy for the hon. Minister that due to shortage of wagons, they could not transport these items. It is a correct thing. The coal is not available; the wagons are not available. If the wagons are available, the coal is not there. The hon. Minister says that the furnace oil is there, the kerosene oil is there but the wagons are not available. What have we to do? It is for the Government, the concerned, Ministers, to sit together and draw up a plan as to how to transport these essential items. The hon. Minister has to tell us what arrangement, in future, he is going to make with the Minister of Railways to see that there is no shortage of wagons for carrying furnace oil and kerosene oil.

Regarding the consumption of kerosene, I think, the hon. Minister must be aware that in Calcutta, in West Bengal, there is load Shedding for 8 to 10 hours every day. If there is no electricity, what is the public going to use? They are going to use kerosene in their houses for lamps, lights or for other things." Therefore, the consumption of kerosene has increased because of the non-availability of electricity. This is also one reason. The hon. Minister has stated in the statement that 3.63 million tonnes was the consumption during the period April, 1978 and February, 1979 as against the allocation of 3.59 million tonnes. There is a very slight increase in the consumption. It is not very much. Therefore, to say that the consumption has gone up is not correct.

In view of all this, I want that the hon. Minister should tell the House by what time it will be possible to regulate the supply of kerosene oil and furnace oil and, secondly, what steps he has proposed or he is going to take to see that these essential itms do not go underground and that the consumer of kerosene have not to pay high prices for the industrial units have to stop production for want of furnace oil.

SHRI H. N. BAHUGUNA: I must, at the outset, say one thing. The nation will have to learn to live within its resources. This year on petroleum and petroleum products, all I can promise the country is that this Government has tried its best to provide the nation its requirement at the last year's level in spite of the fact

[Shri H. N. Bahuguna]

that we are short of crude because of the Iranian situation. We cannot go on increasing our demand of furnace oil, for example. In the 1973 price hike, the entire industry was asked to come to coal. From 1973 till 1977-78 there was a negative growth rate—beginning with minus 5 per cent in 1975-76 to minus 7.8 per cent in the year 1977-78. You will, therefore, see that this spurt in furnace oil business is a recent affair, caused by the international situation, caused by the shortage of coal. Suddenly we are having an increase of 8.6 per cent growth rate. We are trying to bear with it. But I must tell hon. Member Mr. Damani and the House through you, Sir, that the Government is not committed, because of our inability—we wish we could do it—to foot the bill on account of load-shedding, to foot the bill of energy on account of shortage of coal or coke or other fuel. We are really, in shortage in this field. Therefore, the other sources of energy which are in abundance the country have to come into play and this particular scare source of energy should not be strained in the manner indicated by Mr. Damani.

AN HON. MEMBER What is the other source?

SHRI H. N. BAHUGUNA: The other source, as the hon. Member knows, is coal. Coal in this country is in abundance. The hon. Prime Minister has assured the House that we are trying to manage things in a manner that coal is reached everywhere. I am also a member of that Committee which has been constituted to monitor all this and we are trying to pull up things as much as we can to make good, or meet, this type of difficult situation.

So far as Mr. Damani's information or question about closure is concerned, I quote this on the authority of the Director-General of Technical Development, Energy Conservation Division of the Ministry of Industry, who keeps the records about this. I have his authority through this letter. With regard to our enquiries made from him, he has stated in his letter:

"While admittedly there has been shortage of f.o. at some of the pockets in the country at times, as far as the DGTD are aware, there has been no closure of industrial units on this account except one instance in Maharashtra, the International Rubber and General Industries Private Limited, which has reported in the middle of March closure of the unit on account of shortage of f.o. f.o. is consumed by the industry and the power sector to the extent of about four million tonnes per annum. This requirement is met from indigenous source supplemented by import...."

Import is 25 per cent.

"...The f.o. offtake in the last four years has been like this..."

In 1978-79, upto December, we have given more than what we had given in the last year. We canot give more. We will be in trouble in the coming years if we do not manage our energy economy, energy budget, in a proper manner. It is just not available.

So far as load-shedding and other factors are concerned, I repeat, we are not obliged, or, we are not in a position to oblige, the industry or the nation by rushing diesel oil, kerosene oil and furnace oil wherever the real source of energy is not in existence or is not available. We will not be able to do it. I would not make any tall promise. All I can say is that it will be our endeavour to see that supply of furnace oil, kerosene oil and diesel is maintained at least at the last year's level. Again I repeat that the State Governments should take care of the distribution system; so that the period of difficulty and distress is overcome with the cooperation of all concerned.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay—North-East): I would like to draw the attention of the Minister to the fact that Bombay city

is a great city because it happens to be the city of the Prime Minister and before him, Mahatma Gandhi and even other countries' leaders like Mohd. Ali Zinnah and the recently executed Zulfiquar Ali Bhutto come from Bombay. And I also represent Bombay... (*Interruptions*). And the Minister also frequently comes to Bombay.

13 hrs.

What I am surprised is that Bombay is now experiencing long queues for kerosene, particularly, in the slum areas. In the well-to-do areas there is no problem. It is the slums which are suffering. First I want to know from the Minister what he is going to do to ensure an equitable distribution of kerosene in Bombay within the city itself—whatever quota you give... (*Interruptions*) I am sure he will give, otherwise we will *Gherao* him when he comes.

AN HON. MEMBER: He will not come to Bombay.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: This is particularly unfair to Bombay, Sir, because 50 per cent of the crude oil is produced by Bombay High. Out of Bombay it goes and Bombay itself starves... (*Interruptions*) Yes, we are all Indians. Of course, you are less than others as you have extra-territorial loyalties.

The fact of the matter is: as it is said, water, water everywhere but no water to drink, so also oil, oil everywhere around Bombay but there is no oil available for the citizens of Bombay and, therefore, some equity in relationship with the rest of the country also has to be maintained.

I want to know from the Minister what does he mean by saying, "The rate of consumption has shown an upward trend because of inadequate availability of coal at the consuming locations." What is he doing specifically to remove these imbalances he has mentioned? I want to know what steps he has taken in consultation with the Coal Ministry and other Ministries.

(2) He says, 'It has not been possible to import furnace oil and kerosene to the required extent.' What is the percentage of shortfall and what is the tonnage of the shortfall in these commodities? This is a very vaguely and nicely-worded statement. He is a clever Minister and I have the highest respect for him and I have also the deepest appreciation of his ability to get out of tight corners. So I want him to spell out what exactly the shortfall is.

Then he says, 'However, production at the Bombay refineries is running at the anticipated level since the last week of March and imported product has also arrived. It is expected that all these will help in easing the situation.' What does he mean by saying 'it will ease the situation?' When exactly will Bombay feel the easing of the situation? I want to know all this so that I can tell the citizens of Bombay that I have got an assurance from the Minister.

SOME HON. MEMBERS: Very well.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Finally he says:

> "As regards kerosene, about 40 per cent of the total consumption in the country today is imported. The overall availability of kerosene in the country has been affected due to delays in receipts of the product from USSR under the Trade Plan."

A Minister like Bahuguna—and having delays from USSR? How can it be?...

AN HON. MEMBER: Now he has come to the real point.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I want to know why the delays have taken place. What are the other countries besides Iraq and Libya which he has explored? Does he know, for example, despite his ideo-

[Dr. Subramaniam Swamy]

logical inhibitions, that China has got lots and lots of oil? Is he prepared to explore receiving oil from China in exchange for some of the things in which we are surplus?...

AN HON. MEMBER: In exchange for Dr. Swamy.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: After all, if he is willing to take oil from Iraq and Libya and the USSR, despite the delay—I want to know why there is delay—why he has not explored the possibility of importing crude from China, unless he has some aversion to China? I want to know.

Sir, the Prime Minister wrote a letter a few days ago to all the States that they must reduce the consumption of oil by 15 per cent. What is the underlying logic behind this?

So, Sir, these are my pointed questions and I hope he will answer them to our satisfaction.

SHRI H. N. BAHUGUNA: Sir, I too have as much respect for the hon. Member's capability to detect the cleverness and out-theroding herod so far as that is concerned. He is quite right. I have the greatest feelings for Bombay. Bombay is a miniature India; there is no other town in this country which has that type of culture, Bombay culture. Of course, Calcutta is emotionally and if I may say so, philosophically and economically, the nerve-centre of India. But, Bombay remains Miniature India in a measure in which no other city is. I therefore do have; with all respect to Dr. Subramaniam Swamy, an obligation—the Government of India owes an obligation to Bombay because of its composition and because of the way in which it is composed. It is a miniature state in many other ways for many people. It is the biggest towns in many ways. Therefore, we have got to take care of Bombay. But, I want to tell him that his question is misdirected when he is talking about non-availability of crude because of the method of supplying kerosene to the slum areas. I have said it earlier and I would like to repeat it. I wrote a letter to the Chief Minister to following this I would again remind him, Shri Sharad Pawar, that if Jotirpatti in Bombay is tormenting for want of kerosene, then it should be a matter of regret to which I shall certainly draw the attention of the Government of Maharashtra. Dr. Subramaniam Swamy may pull that Government no less than mine, perhaps more than me.

Sir, I must also say that a city which has a representative like Dr. Swamy cannot have his interest ignored by any one except at his own peril. Who is going to do it?

Now, Sir, so far, the hon. Member Dr. Swamy talked about that in spite of Mr. Bahuguna being here, U.S.S.R. has not given the supply of crude. Well, Sir, it is just like saying 'old habit dies hard'. This is one of his old phobias. I must tell him that once he asked me a question and I must share with this House. He said 'Mr. Bahuguna is very much pro-Russian'. I told Dr. Swamy that it is the misfortune of this country that many feel that you are all pro-Americans. I say that both are wrong; both of us are Indians whatever serves the Indian interests. I am telling that we are friendly to certain countries and we are interested in our nation's interest. You must remember that they stood by us in times of needs. Anyway, I won't go into the whole thing.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: It is an economic blunder.

SHRI H. N. BAHUGUNA: So far as supply of crude from the Soviet Union is concerned, there is a freezing during the winter. It is even terrible and during winter, they in turn, failed. They also were affected because of the events in Iran. They received a lot of gas from Iran. They were affected because of events

in Iran. So, charity begins at home. They have promised that they will make up that. They are going to do the shipment. I hope things will be all right. We know the kerosene oil needs. As far as purchase of crude oil is concerned, the hon. Dr. Subramaniam Swamy's suggestion about getting crude from China is something to which I have not exception. There is nothing wrong about it. I have tried. I spoke to the Ambassador of U.S.A. in India. I requested him to come to me. He could not come. I requested him, whether he would be able to help us. I have gone to every body whoever is here. But the point is that we are not able to say whether with the oil that we can refine, we would be able to digest. With the type of crude oil available there with the salt-content and with so many varieties with specific gravity and so many things, I do not know whether we will be able to refine oil here with that type of crude. Nevertheless, I will certainly exchange the hon. Member for oil received by India from China!

MR. DEPUTY-SPEAKER: It will be a great loss.

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, with all the sympathy at my command, I pity the Minister of Petroleum for the unsatisfactory statement that he has laid on the Table of the House. It is just like a shuttle-cock logic of putting the blame in the other court. After reading the entire statement it is clear that the situation is going to be endemic. This situation is not going to improve very soon. If this is the situation at this moment, of the year, I am afraid, what is going to happen in the middle of the year when the monsoons begin. Just earlier as Members mentioned, that there are queues for oil in Bombay, in Madhya Pradesh also there are inaccessible areas in the interiors where crude oil has to be assured before the monsoons.

Sir, a few years back many industries were asked to switch over from coal to petroleum products. Further, has the government made any in-depth study in this sudden increase of 8 per cent in the consumption of furnace oil? How has it happened? I am afraid that the government which is going ahead with industrialisation plan and opening district. Industries Centres what are their projections for the future? How much petroleum products and furnace oil will be required over the next five years? There is a fear expressed by the chairman of the Millowners Association. But we were told that only one rubber factory has been closed but I must tell that many are facing closure. What assurance can we give that in the coming two to three months they will not be allowed to be closed. I would beseech upon the Minister to carry on certain more research on the background of shortage of fuel. Efficient utilisation of available petroleum products should be insisted upon in industries. I quote what the Industrial Adviser Directorate General of Technical Development said:

> "He referred to the Standing Committee on Furnace oil set up by the Government to make an in-depth study of switch-over from furnace oil to coal. Some mills which would be converted are, however, located in congested residential areas and this would give rise to pollution problems."

Therefore, my question to the hon'ble Minister would be: 'what are their projections for the next three to four years? How much would be the production programme? How much you expect to get from the foreign countries? What will be available for distribution to the industries and also the consumers?

[Dr. Vasant Kumar Pandit]

Whether the new industries and the existing ones would be assured of their requirements? Also let us know once for all whether you want to have petroleum product for furnaces or you want to go to coal. The overall picture is so mixed-up that I would ask the hon'ble Minister that a Plan has got to be drawn with regard to the use of furnace oil. In Bombay where the traffic is so congested the trucks cannot carry coal. Therefore, the overall picture which emerges from the statement is not very encouraging. I am afraid that some assurance should be given to the industries that the required quantity for production will not be affected because of want of furnace oil. The hon. Minister should draw up a plan—a Blue Paper—with regard to these industries. If he has not got sufficient furnace oil, let him ration it to a certain extent, to the textile industries etc. Let us have a proper plan to that effect. So, I want to know how they are going to face this endemic problem in the remaining six months of the current year.

SHRI H. N. BAHUGUNA: The last part of the hon Member's question is this. He asked, what are you going to do about the energy supply to the industries. This is a problem which is being handled by the Director General of Technical Development and the Energy Conservation Division, in the Ministry of Industries. They are looking into it. I don't have the ready information just now with me. But I can communicate the advice contained in the question of the hon. Minister for Industries.

Now, so far as the other point is concerned, he asked, how much we will be able to supply, at what level and so on. Let me tell him that we will endeavour to supply at last year's level, in spite of the shortages now in the international market. Let me inform him that I am not accepting any new demand of furnace oil at all. We have told the State Governments about it. We have told the Ministry of Energy that it will not be possible to create oil. In this country we don't have any synthetic method of creating oil. That sort of method is not yet available with us. It is a scarce material. Now let us see what we can get from elsewhere. Many countries of Europe and the nations of the European Economic Community have reduced industrial and domestic uses of petrol and petroleum products by 15 per cent. They have reduced that much. We will have to find out methods to do that. The industry and consumers will have to find out the methods to do that. I hope that they will be able to do that.

Then he asked about the anticipated production of 1978-79. I can give that information. Our plan was to produce in 1978-79 2.70 MT of Kerosene oil and 3.53 MT of furance oil. But the actual production which we now anticipate is this, 1979 is still left and we have some months to go. Our production is likely to be 2.55MT for Kerosene oil or a little less and 3.42 MT for fuel oil or a little less. So, this is the situation. We are increasing imports to the extent of possible availability to make up for shortage. Actual import in 1978-79 is 1.42 MT of Kerosene oil and 0.90 MT of Furance oil. But this type of a situation remains fluid because of non committal of crude oil and non-committal of crude oil prices. OPEC countries have raised the rate from ten pointsome thing to fourteen and a half. OPEC countries have decided to put a premium over these four dollars per barrel. The OPEC market priec is 28 dollars per barrel, I have no quarrel with OPEC countries. They are free to determine at what level they will sell their only material. Because they have nothing else to sell. But our trouble is this. We have got to see the financial implications of depending upon this source of energy and we have to see the availability of resources before we can make any commitment. I hope by the time my Ministry's Budget comes for

discussion in the House I would have come back from my foreign visit where I am going to make my efforts in search of oil and I hope that the goodwill and the good wishes of this honourable House will be with me in my efforts to do the needful.

13.20 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Hundred and Eighteenth and Hundred and Twenty-third Reports

SHRI P. V. NARASIMHA RAO (Hanamkonda): I beg to present the following Reports of the Public Accounts Committee:—

(1) Hundred and eighteenth Report on Action Taken by Government on the recommendations of the Committee contained in their Seventy-first Report relating to Posts and Telegraphs.

(2) Hundred and twenty-third Report on Paragraph 47 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1976-77, Union Government (Civil), Revenue Receipts, Volume II, Direct Taxes on Voluntary Disclosure of Income and Wealth Scheme, 1975 relating to the Ministry of Finance (Department of Revenue).

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

Eighteenth and Nineteenth Reports

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I beg to present the following Reports of the Committee on Public Undertakings:

(1) Eighteenth Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Seventh Report of the Committee on Central Inland Water Transport Corporation——Objectives and River Services.

(2) Nineteenth Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Ninth Report of the Committee on Central Inland Water Transport Corporation——Mismanagement in Organization, Administration and Financial Matters.

13.22 hrs.

DEMAND FOR GRANTS, 1979-80—*contd.*

Ministry of Home *Affairs*—*contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Home Affairs.

Shri Manoranjan Bhakta.

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands): Mr. Deputy-Speaker, Sir, one of the objects of the Home Ministry is to provide good administration for the Union Territories and their proper development. As I was saying, what type of Government has been provided to the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands!

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think you had finished your speech yes-

SHRI MANORANJAN BHAKTA: I will conclude just in a few minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: It is absolutely a bad type of Government provided there with iron curtain. When a Member of Parliament duly elected from that constituency is not permitted to use loudspeaker,